विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1378
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईरान संकट में नागरिकों को बाहर निकालने की तैयारी

1378 श्री सुरेश कुमार शेटकर ;

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या विगत काल में संकट ग्रस्त नागरिकों को बाहर निकालने के संबंध में 'ऑपरेशन गंगा' और 'ऑपरेशन कावेरी' जैसे अभियानों से कोई सबक लिया गया है और हाँ, तो ईरान संकट में इस संबंध में इस विषय में वैसी तेजी, स्पष्टता और व्यापकता के अभाव के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने संकटग्रस्त लोगों को बाहर निकालने की समय-सीमा, विमानसेवा के ब्यौरे और सुरक्षा प्रोटोकॉल के विषय में पारदर्शिता तथा वास्तविक समय पर जानकारी की कमी के कारण भारतीय नागरिकों के परिवारों को हुई चिंता की जिम्मेदारी ली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अब तक बाहर निकाले गए भारतीयों की कुल संख्या, अभी भी फंसे हुए लोगों और शेष सभी नागरिकों को वापस लाने की अनुमानित समय-सीमा के संबंध में जानकारी सार्वजनिक करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि हवाई क्षेत्र के बंद होने के दौरान वाणिज्यिक एयरलाइनों पर निर्भरता ने भारत की संकटकालीन सहायता प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है; और

(ड.) क्या इस बारे में किसी स्थायी त्वरित-प्रतिक्रिया निकासी तंत्र का गठन किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ङ) भारत सरकार प्रत्येक निकासी परिदृश्य को उसकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर देखती है। इससे सरकार को सशस्त्र संघर्ष, हवाई क्षेत्र की बंदिश, नियमित उड़ानों के बंद होने जैसी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली है। ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई अभ्यास योजना की मजबूती के प्रमाण हैं। ईरान में भी, संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जून 2025 में 'ऑपरेशन सिंधु' सफलतापूर्वक चलाया गया था। कुल 4415 भारतीय नागरिकों (ईरान से 3597 और इजराइल से 818) को 19 विशेष निकासी उड़ानों (जिनमें 3 भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान शामिल थे) का उपयोग करके निकाला गया, क्योंकि चल रही शत्रुता के कारण नियमित उड़ान सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। जटिलताओं के बावजूद, भारत ऐसे त्वरित निकासी अभियान चलाने वाले पहले देशों में से एक था। विभिन्न निकासियों के प्रश्न में व्यक्त किया गया मत तथ्यों से समर्थित नहीं है।

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार विदेशों में उभरती प्रतिकूल परिस्थितियों पर कड़ी नज़र रखती है और आवश्यकतानुसार सलाह जारी करती है ताकि भारतीय नागरिक अनावश्यक यात्रा से बचें, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें और भारतीय मिशनों के संपर्क में रहें। भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय मिशनों / केंद्रों से संपर्क करने के लिए विभिन्न संचार माध्यम उपलब्ध हैं, जिनमें ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, सोशल मीडिया, टोल-फ्री हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर शामिल हैं। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत में, 5 जनवरी और 14 जनवरी 2026 को सलाह जारी की गई थी ताकि भारतीय नागरिक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचें, उचित सावधानी बरतें, विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहें और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने और जुड़े रहने के लिए दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर नज़र रखें।

वर्तमान में, छात्रों, कामगारों, नाविकों आदि सहित लगभग 9,000 से 10,000 भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं। भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संपर्क में है। मौजूदा स्थिति में, वाणिज्यिक उड़ानें जारी रहने और ईरानी हवाई क्षेत्र के खुले रहने के कारण सरकार ने अभी तक निकासी अभियान शुरू नहीं किया है। सरकार स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है।

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के सामने आने वाली संकट स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने 2021 में 'रैपिड रिस्पांस सेल (आरआरसी)' नामक एक समर्पित विंग की स्थापना की। निकासी अभियानों के अतिरिक्त , आरआरसी समग्र सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए राहत सामग्री की आपूर्ति, एचएडीआर अभियानों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की तैनाती और अन्य पुनर्वास प्रयासों सहित सहयोगी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

आरआरसी स्थानीय मिशन, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, नागर विमानन मंत्रालय आदि सहित संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए निकासी अभियानों का समन्वय करता है। निकासी के दौरान, भारतीय नागरिकों को सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यालय और विदेशों में 24x7 नियंत्रण कक्ष संचालित किए जाते हैं।

मंत्रालय निकासी अभियानों की योजना और क्रियान्वयन के दौरान उपयोग के लिए एक डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधान भी विकसित कर रहा है। यह समाधान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बुनियादी और वास्तविक समय की जानकारी के साथ-साथ वर्तमान स्थान दर्ज करने और संकट की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस समाधान का उपयोग 2025 में निकासी अभियानों के दौरान प्रायोगिक आधार पर किया गया था।

*****